



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]
No. 77]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2004/वैशाख 6, 1926
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2004/VAISAKHA 6, 1926

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन)

(संशोधन) विनियमन, 2004

सं. दिल्ली : राडेविबोर्ड.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके साथ धारा 30 और धारा 31 को समाहित करते हुए और इस तरह से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक-मण्डल, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना, राडेविबोर्ड/विधि/4401 दिनांक 12 जुलाई, 2000 के रूप में प्रकाशित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियमन, 2000 के भाग III - खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. लघु शीर्षक एवं आरंभ :

- (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।
- (2) जब तक विनियमों में अन्यथा न कहा जाए, इसके प्रावधान भारत के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियम, 2000 में संशोधन :

- (1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (घ) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(घ) “न्यायालय” का अर्थ है—जनपद में मूल अधिकार-क्षेत्र की प्रमुख दीवानी अदालत (जिसमें उच्च न्यायालय अपने मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र के कारण शामिल हैं) जिसके अधिकार-क्षेत्र में आता है कि वह दावों की विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करे यदि वे वाद की विषय-वस्तु से संबंधित हैं, किन्तु इसमें ऐसी कोई भी दीवानी अदालत शामिल नहीं है जो ऐसी प्रमुख दीवानी अदालत, अथवा अन्य लघु वाद-अदालत से किसी भी स्तर में कम हो।”

(2) विनियम 4 में -

(क) उप-विनियम (1) में,

- (i) खंड (क) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) आवेदन के बारे में जो खंड (i) के अधीन सहायता मांगते हुए, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ऋण अथवा अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में धरोहरित, निक्षेपित, दृष्टिबंधित अथवा हस्तांतरित संपत्ति से संबंधित ऐसे आदेश पारित करता है जो इसे ऐसे ऋण अथवा अग्रिम की अंतिम वसूली को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और उचित लगे।”

(ii) खंड (ख) में, “खंड (ग)”, की अभिव्यक्ति हेतु, अभिव्यक्ति “खंड (iii)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में, “खंड (ख)”, की अभिव्यक्ति हेतु, अभिव्यक्ति “खंड (ii)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ख) उप-विनियम (4) को हटा दिया जाएगा।
- (3) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में, "विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन" के स्थान पर, "विनियम 7 के अधीन" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (4) विनियम 10 में, "विनियम 7 का उप-विनियम (1)" की अभिव्यक्ति के लिए "विनियम 4 का उप-विनियम (1)" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दीपक टिक्कू, प्रबन्ध निदेशक
[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/132/04]

**NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2004

**The National Dairy Development Board (Enforcement of Claims)
(Amendment) Regulations, 2004**

No. DEL:NDDB.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), read with Section 30 and Section 31 thereof, and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors of the National Dairy Development Board hereby makes the following Amendments to the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000 published in Part III - Section 4 of Gazette of India, Extraordinary, as Notification NDDB/LEGAL/4401 dated 12th July, 2000, namely :—

1. Short title and commencement :

- (1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) (Amendment) Regulations, 2004.
- (2) Save as otherwise provided in the regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000:
In the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000 :—

- (1) In Regulation 2, for clause (d) of Sub-regulation (1), the following clause shall be substituted, namely :—
“(d) “Court” means the principal civil court of original jurisdiction in a district (which includes the High Court in exercise of its original civil jurisdiction), having jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of the claims if the same have been the subject matter of a suit, but does not include any civil court of a grade inferior to such principal civil court, or any court of small causes.”
- (2) In Regulation 4.—
 - (a) in Sub-regulation (1),
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—
“(a) in case of an Application seeking relief under clause (i) thereof, pass such appropriate order, concerning the property pledged, mortgaged, hypothecated or assigned to National Dairy Development Board as security for the loan or advance, as it may deem fit and proper to ensure the ultimate recovery of such loan or advance.”
 - (ii) in clause (b), for the expression “clause (c)”, the expression “clause (iii)” shall be substituted;
 - (iii) in clause (c), for the expression “clause (b)”, the expression “clause (ii)” shall be substituted;
 - (b) sub-regulation (4) shall be omitted.
- (3) In Regulation 9, in sub-regulation (1), for the expression “under sub-regulation (1) of regulation (7)”, the expression “under regulation 7” shall be substituted.
- (4) In Regulation 10, for the expression “sub-regulation (1) of regulation 7”, the expression “sub-regulation (1) of regulation 4” shall be substituted.

DEEPAK TIKKU, Managing Director
[No. ADVT-3/4/Exty/132/04]